*आयात उपायों की प्रभावकारिता : चुनिंदा वस्तुओं का विश्लेषण**

भारत ने आयात-संबंधी कई उपाय किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतया व्यापार भागीदारों द्वारा अपनायी जा रही अनुचित व्यापार प्रथाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप किए गए उपाय हैं। इस अध्ययन में, दो परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है। पहला, क्या आयात उपायों से आयात मात्रा पर वांछित प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आयात उपायों को लागू करने के बाद कीमतें कैसे व्यवहार करती हैं। 2013 से 2019 की अवधि के लिए 119 आयात वस्तुओं पर कमोडिटी स्तर के पैनल डेटा का उपयोग करते हुए, अध्ययन में एक समुचित विपरीत तथ्यपरक डेटा प्राप्त करने और आयात उपायों के कारण-संबंधी प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विभिन्नता में भिन्नता विधियों को लागू किया गया है। यह पाया गया है कि आयात उपायों का आयात वस्तुओं की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनकी मुद्रास्फीति पर नहीं।

I. परिचय

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, देश के प्रमुख उद्योगों, वस्तुओं और रोजगार जैसे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को लेकर व्यापार संबंधी उपायों का सहारा लेना, संरक्षणवाद के प्रति झुकाव को दर्शाता है। टैरिफ बढ़ने, आयात कोटा, उत्पाद मानकों, प्रति-पाटन (एंटी-डंपिंग) शुल्क और प्रतिकारी (काउंटर्वेलिंग) शुल्क संबंधी जांच के संदर्भ में ये नीतिगत उपाय भिन्न-भिन्न देशों में स्पष्ट दिखते हैं। संरक्षणवाद पर बहस आर्थिक साहित्य के लिए कोई नई बात नहीं है। 1848 की शुरुआत में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के शब्दार्थ अनुसंधान में उल्लेख है कि संरक्षणवादी नीतियां वे साया हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे भी मुक्त व्यापार की दिशा में नीति के पक्ष में नहीं थे। हालांकि, कई विद्वानों ने देशों के बीच मुक्त व्यापार का समर्थन किया है और इसे संसाधनों की न्यूनतम विकृति के साथ उचित आवंटन में इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा साधन माना है (कुछ नाम लिए जा सकते हैं, जैसे, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, रिकार्डो)। वैश्वीकरण के साथ देशों के एकीकरण को न केवल वस्तुओं में अप्रतिबंधित व्यापार के संदर्भ में देखा जाता है, बल्कि अबाधित श्रम आवागमन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में भी देखा जाता है। हालांकि, हाल के दिनों में, नीति-निर्माताओं के बीच अंदरूनी नीतियों को लेकर अधिक जोर दिया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर संरक्षणवाद पर चिंता व्यक्त की है, जिससे प्रतिशोधात्मक उपायों के बढ़ने की आशंका है जो उल्टे नतीजतन होने वाली व्यापार खामियों से जुड़ी लागत को बढ़ाता है। जैसा कि पहले कहा गया था, दोनों उन्नत और उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि के बाद विभिन्न रूपों में व्यापार संरक्षणवादी उपायों को विस्तृत रूप में अपनाया है।

ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लागू कुल व्यापार संरक्षणवादी उपायों में से लगभग 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पण्य व्यापार को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट (2019) की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ बढ़ोतरी का सामना करने वाले उत्पादों के आयात का मूल्य भारत के मामले में लगभग 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निर्यात और आयात (माल) दोनों के मामले में सभी प्रकार के संरक्षणवादी उपाय (दोनों टैरिफ और गैर-टैरिफ) 2009 के बाद से बढ़ रहे हैं (चार्ट 1)। भारत को प्रभावित करने वाले संरक्षणवादी उपाय इसके द्वारा लागू किए गए उपायों से 5 गुना अधिक हैं। भारत द्वारा माल व्यापार को लेकर आयात प्रतिबंधात्मक उपाय का सहारा लेने का सिलसिला 2016 और 2017 में बहुत घट गया, लेकिन बाद में घटने से पहले 2018 में फिर से बढ़ा (सारणी 1)।

भारत के मामले में, आयात के उपाय या तो सरकार के प्रमुख 'मेक इन इंडिया' योजना को बढ़ावा देने या कुछ क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स) में प्रचलित उल्टी शुल्क संरचना के मुद्दे का हल करने के उद्देश्य से किए गए हैं। अन्य उपाय व्यापार भागीदारों द्वारा अपनाई गई डंपिंग प्रथाओं के प्रति जवाबी कार्रवाई स्वरूप किए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, अध्ययन में प्रमुख सवालों की जांच की गई है कि इन उत्पादों की आयात मात्रा और घरेलू कीमतें आयात प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रति कैसा बर्ताव करती हैं।

यह बहुत मुमकिन है कि आयात प्रतिबंध - जब घरेलू माँग घरेलू आपूर्ति से पूरी नहीं होती है – आयात में कटौती की वजह

---

* यह लेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के सोनम चौधरी और राजीव जैन द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने विचार हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेखक, श्रीमती रेखा मिश्र; श्री धीरेन्द्र गजभिये; श्री प्रभात कुमार और श्रीमती मधुच्छन्दा साहू के बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

चार्ट 1: भारत द्वारा नवंबर 2008 से किए गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय

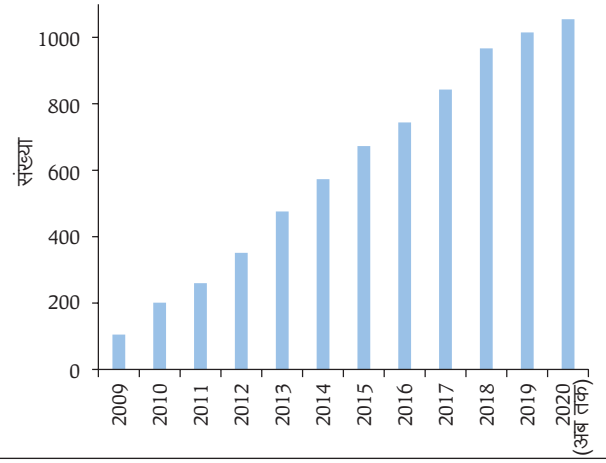

सारणी 1: वर्ष-वार व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय (संख्या)

वर्ष	भारत को प्रभावित करने वाली	भारत द्वारा लागू
2009	429	89
2010	391	96
2011	399	59
2012	451	91
2013	454	125
2014	523	97
2015	639	100
2016	524	71
2017	559	99
2018	645	124
2019	308	48
2020 (अब तक)	125	40

टिप्पणी : ग्लोबल ट्रेड अलर्ट (जीटीए) डेटाबेस ने 24 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट किया है कि नवंबर 2008 से किए गए कुल संरक्षणवादी उपायों की संचयी संख्या 1055 है। जीटीए द्वारा यथा परिभाषित अनुसार, इस डेटा में सभी प्रकार के उपाय शामिल हैं जिनमें व्यापार सुरक्षा (अर्थात, प्रति-पाटन शुल्क), टैरिफ उपाय, निर्यात प्रोत्साहन (ब्याज सहायता, छूट, आदि), स्थान विशेष की आवश्यकता, व्यापार वित्त, उबारना/राज्य सहायता उपाय एवं अन्य आते हैं।
स्रोत : ग्लोबल ट्रेड अलर्ट से संकलित।

से उन वस्तुओं की घरेलू कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, परीक्षण योग्य परिकल्पनाएं इस प्रकार हैं, जैसे (ए) क्या ये आयात संबंधी उपाय आयातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और (बी) क्या ये उपाय आयातों को कम करके उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाते हैं।

तदनुसार, अध्ययन को चार भागों में बांटा गया है। भाग II में संबंधित साहित्य का स्नैपशॉट दिया गया है। भाग III में अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा पर चर्चा की गई है। अनुभवजन्य निष्कर्षों को भाग IV में शामिल किया गया है और अंततः भाग V में निष्कर्ष निकाले गए हैं।

II. रचना की समीक्षा

आर्थिक रचना में, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के खुलेपन के स्तर पर काफी चर्चा की गई है। मुक्त व्यापार के समर्थकों ने सुचारू रूप से काम कर रहे प्रतिस्पर्धी बाजार के तर्क का समर्थन किया है, जो न केवल जहां तक संभव हो सके सर्वोत्तम तरीके से संसाधनों का आवंटन करेगा, बल्कि उत्पादकता लाभ भी पैदा करेगा। यह तर्क दिया जाता है कि व्यापार पर शुल्क और प्रतिबंधों के रूप में बाजार की विकृतियां उपभोक्ताओं सहित संपूर्ण प्रणाली के लिए अक्षमता पैदा करके इष्टतम समाधान से उत्पादकों को विचलित करती हैं। जबकि दूसरी ओर, व्यापार संरक्षणवाद के समर्थकों का तर्क है कि व्यापार प्रतिबंधित नीतियों का मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण पर टिका हुआ है।

व्यापार संरक्षणवाद के इतिहास में झांककर देखें तो पता चलता है कि उसकी शुरुआत आज से बहुत पहले सन 1567 में वणिकवाद के रूप में हुई थी। फ्रांस वह पहला देश था जिसने अंतर्राष्ट्रीय होड़ से ल्योन रेशम की रक्षा के लिए व्यापार संबंधी उपायों को लागू किया था। अधिकांश 16वीं शताब्दी के दौरान और 18वीं शताब्दी के अंत तक, कई देशों ने वणिकवाद के सिद्धांत को अपनाकर अनुकूल व्यापार संतुलन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस अवधि के दौरान अधिकांश यूरोपीय देशों ने घरेलू उद्योग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संरक्षणवादी नीतियों का आयातों पर विभिन्न टैरिफ, कोटा के रूप में इस्तेमाल किया। इस युग का अंत तब हुआ जब ब्रिटेन, जो उस समय की सबसे बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी, ने विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। विश्व की अर्थव्यवस्था उदारीकृत व्यापार नीतियों की ओर अग्रसर हुई; हालांकि, व्यापार के सिद्धान्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आधारित थे, जिसमें मुक्त-व्यापार संधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया।

1955-56 में अमेरिकी टैरिफ कटौती योजना के तहत लागू टैरिफ परिवर्तनों के कारण के अनुक्रम पर प्रकाश डालते हुए क्रेइनिन (1961) द्वारा किए गए एक मौलिक अध्ययन में पाया गया है कि टैरिफ कम होने से आयातित वस्तुओं की कीमतें घटती हैं और आयात मात्रा बढ़ती है। 1960 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक अन्य लोकप्रिय मुक्त-व्यापार उन्मुख वाणिज्यिक समझौता हुआ था, अर्थात, कॉबडेन-शेवेलियर संधि[1]। इस संधि को 'मुक्त व्यापार महामारी' कहा गया, क्योंकि इसने यूरोपीय महाद्वीप में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की कई श्रृंखलाओं को प्रेरित किया, जो सदियों से संरक्षणवादी नीतियों का पालन कर रहीं थीं (लेज़र, 1999 और विश्व व्यापार संगठन, (डब्ल्यूटीओ))।[2] समझौतों के इस व्यापक नए नेटवर्क, जिसमें पारस्परिक नीतियों को शामिल किया गया था, ने टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के रूप में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए एक मजबूत दृष्टि का निर्माण किया। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के 8 दौर के बाद, 1995 में यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूटीओ के रूप में व्यापार को बढ़ावा देने वाले एक अलग निकाय का निर्माण किया जाए जिसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के दायरे में विस्तार करते हुए उसमें सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल किया जाए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद से, विश्व जीडीपी के हिस्से के रूप में वैश्विक व्यापार 1995 में 43.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019[3] में 60.4 प्रतिशत हो गया है। विश्व अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट के दौरान तेज मंदी देखी गई और कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने घरेलू फर्मों की सुरक्षा (रोड्रिक, 2009; बोउन, 2011) की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों को अपनाया। बढ़ते संरक्षणवाद के हालिया उदाहरणों में से एक यूएस-चीन टैरिफ वॉर है।

साहित्य में, शोधकर्ताओं ने आयात में गहरी पकड़ और घरेलू अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को लेकर मोटे तौर पर दो नज़रिया पेश किया है। एक बहस यह है कि आयात भेद्यता ज्यादा होने से वृद्धि पर दबाव आता है क्योंकि आयात मूल्य कम होने से घरेलू वस्तुओं की मांग में कमी आती है और बदले में इससे उत्पादन और उद्योग सिकुड़ने लगता है। दूसरे विचार के अनुसार अधिक विदेशी होड़ के साथ आयात में गहरी पकड़ से अति-स्पर्धा का माहौल पनपता है, जो घरेलू फर्मों को निवेश करने और लाभप्रदता बेहतर करने के लिए मजबूर करता है, लिहाजा संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक व्यापार मॉडल व्यापार पर टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है और इस संबंध में व्यापक मत है कि टैरिफ विदेशी वस्तुओं को महंगा कर देता है और आयात की मांग को कम करता है। इनमें से अधिकांशनों अध्ययन देश-स्तर के डेटा पर आधारित हैं न कि पण्य स्तर के डेटा पर। केवल कुछ एक अध्ययन में पण्य स्तर पर आयात की मात्राओं और मुद्रास्फीति पर टैरिफ के प्रभाव को लेकर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। पूर्व के कुछ अध्ययनों में व्यापार में खुलेपन के चलते उत्पादन मुद्रास्फीति में तालमेल को लेकर साक्ष्य प्रदान किए गए हैं। मुद्रास्फीति और व्यापार खुलेपन के बीच काफी नकारात्मक संबंध होने का साक्ष्य मिलता है (रोमर, 1993)। एक अन्य अध्ययन, 1973 से 1998 तक के पैनल डेटा का उपयोग कर, के अनुसार व्यापार में खुलापन अल्प समय में देशों की मुद्रास्फीति को रोकने में अहम भूमिका अदा नहीं करता है (अल्फ़ारो, 2005)। विकासशील देशों के मामले में, देश के खुलेपन और मूल्य स्तर के बीच नकारात्मक संबंध है जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका और बेलजियम के मामले में सकारात्मक संबंध है (किम और बेलाडी, 2005)।

पैनल वीएआर का उपयोग करके हाल में किए गए अध्ययन, जिसमें समष्टिआर्थिक उतार-चढ़ावों पर संरक्षणवाद के प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, में पाया गया है कि संरक्षणवाद समष्टिआर्थिक उद्दीपन के लिए कारगर साधन नहीं है। अध्ययन के मुताबिक कि संरक्षणवाद को लेकर लगाया गया अनुमान आपूर्ति झटका के रूप में काम करता है और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है (बारातियारी एवं अन्य, 2018)। एक अन्य

---

1 इस संधि को क्रांतिकारी माना गया है जिसमें किए गए समझौते के अनुसार 44 मोटे तौर पर परिभाषित ब्रिटिश उत्पादों के आयातों को अनुमति प्रदान की गई है, जो पहले प्रतिबंधित थे। यह समझौता पहला अधिमान्य संधि है, जिसमें बेशर्त सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) बर्ताव एवं अधिमान्य टैरिफ शामिल हैं। इनके अलावा, दो देशों द्वारा टैरिफ में भारी कटौती की गई थी।

2 'उन्नीसवीं सदी के द्विपक्षवाद का वर्णन : कॉबडेन-शेवेलियर नेटवर्क के आर्थिक और राजनीतिक निर्धारक तत्व', विश्व व्यापार संगठन।

3 डेटा में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार को शामिल किया गया है और वर्ल्ड बैंक से पुनः प्राप्त किया गया है। *https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS.* नवीनतम उपलब्ध डेटा 2019 के लिए है।

अध्ययन इन निष्कर्षों को और मजबूत करता है कि आयात टैरिफ में तेज कमी के रूप में व्यापार नीति में परिवर्तन औसतन आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, हालांकि यह प्रभाव विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न होता है (इरविन, 2019)। विद्वानों ने तर्क दिया है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यापार संरक्षणवाद में हाल ही में वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है। कुछ अध्ययनों में अमेरिका और चीन द्वारा टैरिफ में हालिया बढ़ोतरी करने को लेकर जांच करने का प्रयास किया गया है। इनमें से कुछ अध्ययन इस बात पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं कि टैरिफ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के संदर्भ में मांग और कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। इस तरह के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने से मध्यवर्ती और तैयार माल दोनों की कीमतें प्रभावित हुईं, जिस पर अप्रभावित क्षेत्रों की तुलना में शुल्क लगाए गए थे, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आपूर्ति-श्रृंखला नेटवर्क में भारी बदलाव देखे गए थे (अमिती एवं अन्य, 2019)। इसके अलावा टैरिफ लगाए जाने से उसका अमेरिकी घरेलू कीमतों पर पूरी तरह से संचरण हुआ, जिसका आशय है कि घरेलू उपभोक्ताओं और आयातकों पर टैरिफ की मार पड़ी और विदेशी निर्यातकों द्वारा प्राप्त कीमतों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका के मामले में, टैरिफ-युक्त वस्तुओं पर उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप चीन से कम आयात हुआ (निकिता, 2019)। टैरिफ बढ़ोतरी के रूप में अमेरिका और चीन के संरक्षणवाद के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि कीमतों में वृद्धि से अमेरिकी व्यापार प्रवाह में गिरावट आई है और 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है (फज़लबॉम एवं अन्य, 2020)।

वर्तमान अध्ययन सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य से संबंधित है, जो कीमतों और आयात जैसे वृहद-आर्थिक संकेतकों पर आयात उपायों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन व्यापार उपायों के अल्पकालिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले मासिक व्यापार और समष्टिआर्थिक डेटा का उपयोग करता है। इस प्रकार यह अध्ययन व्यापार उपायों के प्रभाव के संबंध में बढ़ते साहित्य में योगदान देता है।

III. डेटा विवरण

अध्ययन में उन चुनिंदा वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिन पर आयात संबंधी उपाय जनवरी 2015 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान लागू किए गए थे। ये उपाय या तो उच्च बुनियादी सीमा शुल्क / प्रति-पाटन शुल्क (बीसीडी/एडीडी) के रूप में या गैर-टैरिफ प्रतिबंध के किसी अन्य रूप में थे। आयात उपाय संबंधी डेटा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और भारत सरकार के केंद्रीय बजट द्वारा जारी अधिसूचनाओं से संकलित किए जाते हैं (सूची के लिए अनुबंध देखें)।

सैम्पल अवधि के दौरान जिन वस्तुओं के संबंध में आयात उपाय किए गए थे उनमें से केवल 50 वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति और घरेलू उत्पादन संबंधी तुलनीय डेटा उपलब्ध थे, जिसे अनुभवजन्य विश्लेषण (ट्रीटमेन्ट ग्रुप) के लिए उपयोग किया जा सकता है। सैम्पल अवधि के दौरान उन वस्तुओं जिन पर आयात उपाय लागू किए गए थे उनके अलावा अध्ययन में 69 वस्तुओं की भी जांच की गई है जो समूह (कन्ट्रोल ग्रुप) में से यादृच्छिक रूप से चुनी गयी आयात वस्तुएं हैं। व्यापक समूह में आने वाली इन वस्तुओं का उन वस्तुओं के साथ या तो समस्तरीय अथवा विषमस्तरीय संबंध है जिन पर आयात संबंधी उपाय लागू किए गए थे। इसलिए, कुल 119 आयात वस्तुओं का सैम्पल लिया गया था। इस अध्ययन के मूल में दोनों श्रेणियों (अर्थात, आयात उपायों सहित और रहित) के आयातों की पार्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित करना है। अध्ययन में जनवरी 2013 से दिसंबर 2019 तक इन 119 वस्तुओं को लेकर कीमत, आयात और उत्पादन संबंधी डेटा जुटाए गए हैं।

मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए, अध्ययन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक/थोक मूल्य सूचकांक के मासिक डेटा का उपयोग किया गया है। चयनित वस्तुओं के आयात का डेटा एमओसी एंड आई के

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस) महानिदेशालय से या तो छह अथवा आठ अंकों के स्तर पर निकाला गया है। घरेलू उत्पादन डेटा मुख्य रूप से एमओएसपीआई से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित हैं। कृषि वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में, रबी/ खरीफ के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा तथा बादाम और अखरोट के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग शुल्क लगाने के पूर्व और बाद के दौरान उत्पादन में औसत वृद्धि के लिए उचित रूप से किया जाता है। अध्ययन में अधिक बारीकी से वस्तु की कीमतों और उत्पादन के संबंध में संगत जानकारी के साथ ही वस्तुओं के आयातों का एक-एक करके मैपिंग किया गया है, जिन पर टैरिफ / गैर-टैरिफ उपाय लागू किए गए थे।

IV. शोधपरक तथ्य और प्रयोगसिद्ध विश्लेषण

कीमतों और कल्याण पर व्यापार उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पारंपरिक व्यापार ढांचा पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार की धारणा के साथ आंशिक संतुलन मॉडल पर आधारित है। सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि टैरिफ, कोटा, स्वैच्छिक प्रतिबंधों आदि के रूप में आयात प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने से आयातित वस्तु की लागत बढ़ जाती है और इसलिए इसकी घरेलू मांग कम हो जाती है। हालांकि, मांग में कमी की तीव्रता मांग और आपूर्ति वक्रों के ढलान पर निर्भर करती है।

यह जानने के लिए कि प्रतिबंधात्मक उपायों ने कैसे आयातों को प्रभावित किया है, प्रथम कदम के तौर पर, हम अध्ययन में विचार की गई समयावधि के दौरान इन वस्तुओं की आयात मात्रा का क्या हुआ उसकी जांच करते हैं। डीजीसीआई एंड एस द्वारा सूचित डेटा हार्मोनाइज़्ड टैरिफ शेड्यूल (एचटीएस) के छह और आठ-अंक स्तर पर आयात मूल्य और आयातित मात्रा देते हैं। ये डेटा छोटी-छोटी लगभग 12,000 श्रेणियों के आयातों के मासिक ब्योरा के लिए हैं।

सारणी 2: सारांश सांख्यिकी : आयात मात्रा में उतार-चढ़ाव

आयात	कुल सैम्पल आकार	व्यापार उपाय लागू करने के बाद आयात मात्रा में परिवर्तन	
		गिरावट	वृद्धि
आयात उपायों के साथ : ट्रीटमेन्ट ग्रुप	50	37	13
आयात उपायों के बगैर (संबंधित वस्तुएं): कन्ट्रोल ग्रुप	69	33	36
कुल	119	70	49

स्रोत : डीजीसीआईएस डेटा पर आधारित लेखकों की गणना।

सारणी 2 में ट्रीटमेन्ट और कन्ट्रोल ग्रुप दोनों वस्तुओं के लिए आयात मात्रा वृद्धि पर आधारित वस्तुओं की सैम्पल संरचना एवं विभाजन प्रस्तुत किया गया है। 50 वस्तुओं, जिन पर आयात प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए थे, में से कुछ वस्तुओं में उपायों के कार्यान्वयन-पश्चात की आयात मात्रा वृद्धि में काफी गिरावट दर्ज की गई। प्राथमिक विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण स्वरूप उभरते हैं। उदाहरण के लिए, 70 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं, जिन पर आयात उपाय लागू किए गए थे, में कार्यान्वयन-पश्चात अवधि में औसतन आयात मात्रा में गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत, कुछ वस्तुओं के लिए, आयात मात्रा में इस तरह के उपाय लागू करने के बाद वृद्धि हुई। चार्ट 2 में प्रतिबंधित अवधि के दौरान दोनों ट्रीटमेन्ट और कन्ट्रोल ग्रुप श्रेणियों के मामले में कैसे आयात-मात्रा वृद्धि व्यवहार करती है के संबंध में जानकारी दी गई है। हॉट-रोल्ड स्टेनलेस स्टील, फाइबरग्लास, एथिल अल्कोहल जैसी वस्तुएं उन वस्तुओं में से हैं, जिन्होंने आयात उपाय के बाद भी उच्च मात्रा में वृद्धि दर्ज की है।

शैलीगत तथ्य आयात उपायों के पूर्व और पश्च कार्यान्वयन में विशिष्ट वस्तुओं की आयात मात्रा में वृद्धि के कुछ रुझान प्रदान करते हैं, जो इस धारणा के अनुरूप है कि इन प्रतिबंधात्मक उपायों के कारण आयात में गिरावट आई है या लागत में वृद्धि के

चार्ट 2: चुनिंदा मदों की औसत आयात मात्रा में वृद्धि

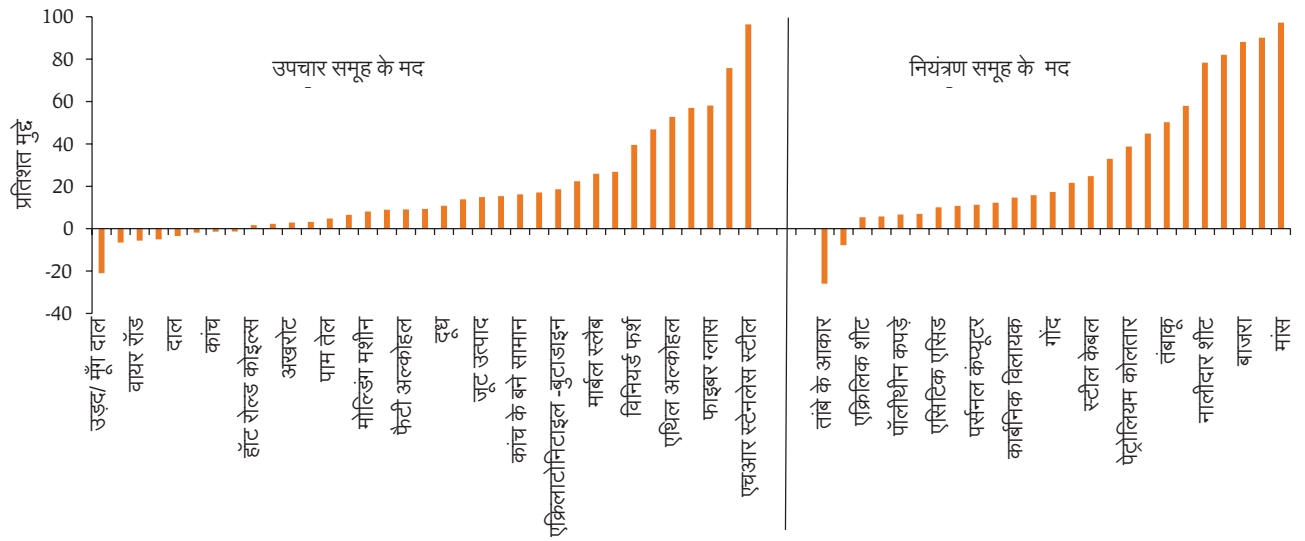

टिप्पणी : केवल उन्हीं आयात वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि दर्शाई गई है जिनका रेंज -100% से + 100% की सीमा में हैं।

कारण घरेलू आपूर्ति वस्तुओं की उच्च उपलब्धता के कारण। सारणी 3 में इन आयातित वस्तुओं के घरेलू मूल्यों से संबंधित प्रारंभिक अवलोकन की जांच के लिए वही कार्य प्रणाली दोहराई गई है। सारणी से यह बात पता चलती है कि उपचार समूह में आधे से अधिक पण्यों में पश्च कार्यान्वयन अवधि में औसतन कीमतों में वृद्धि का अनुभव नहीं हुआ। हालांकि, इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि पाम तेल, सोयाबीन तेल, कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड कॉइल, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों जैसी वस्तुओं की कार्यान्वयन के पश्च उपायों से मुद्रास्फीति दर में तेजी से वृद्धि हुई है (चार्ट 3)। प्रत्यक्षत:, ऐसा लगता है कि आयात उपाय लागू किए जाने के बाद मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया

सारणी3: सारांश सांख्यिकी: मूल्य भिन्नता

पण्य	कुल नमूना आकार	व्यापार उपायों को लागू करने के बाद मुद्रास्फीति में बदलाव	
		कमी	वृद्धि
आयात उपायों के साथ :उपचार समूह	50	27	23
आयात उपायों के बिना (संबंधित मदें): नियंत्रण समूह	69	39	30
कुल	119	66	53

स्रोत: डीजीसीआईएस डाटा पर आधारित लेखकों की गणना

में कोई पैटर्न नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित चर्चा में इसका अनुभवजन्य परीक्षण किया जा रहा है।

आयात मात्रा और मुद्रास्फीति संचलन पर कुछ शैलीगत तथ्य प्रदान करने के बाद, अध्ययन के दो परिणाम संकेतक, अर्थात, मूल्य और आयात मात्रा वृद्धि पर आयात प्रतिबंधक उपायों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक मॉडल निर्दिष्ट करता है। प्रभाव को समझने के लिए, हमने दिनांकित पैनल ढांचे में अंतर-में-अंतर (डीआईडी) का प्रयोग किया, जो नीतिगत परिवर्तनों के आकस्मिक प्रभावों की जांच करने के लिए लोकप्रिय डिजाइनों में से एक है। इस अध्ययन के लिए अनुमान का परीक्षण इस बात से संबंधित है कि क्या आयात उपायों को लागू करने से आयात कम हुआ और विशेष रूप से घरेलू कीमतों में कैसे प्रगति हुई। यह अनुभवजन्य विनिर्देश वस्तुओं के बीच संबंधों को अलग करने का प्रयास करता है जिस पर उपाय लगाए जाते हैं और जिन वस्तुओं पर ऐसे उपाय नहीं लगाए जाते हैं।

इस प्रकार, हमारे मामले में, वस्तुओं के दो उप-समूह हैं, अर्थात्, आयात उपायों (उपचार समूह) के साथ आयात मद और आयात उपाय (नियंत्रण समूह) के बिना आयात मद, जो उत्पाद डमी द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह, प्रत्येक आयातित वस्तु के लिए दो समय अवधि हैं, अर्थात्, प्रतिबंधों के पूर्व और

चार्ट 3: चुनिंदा मदों की औसत मूल्य में वृद्धि

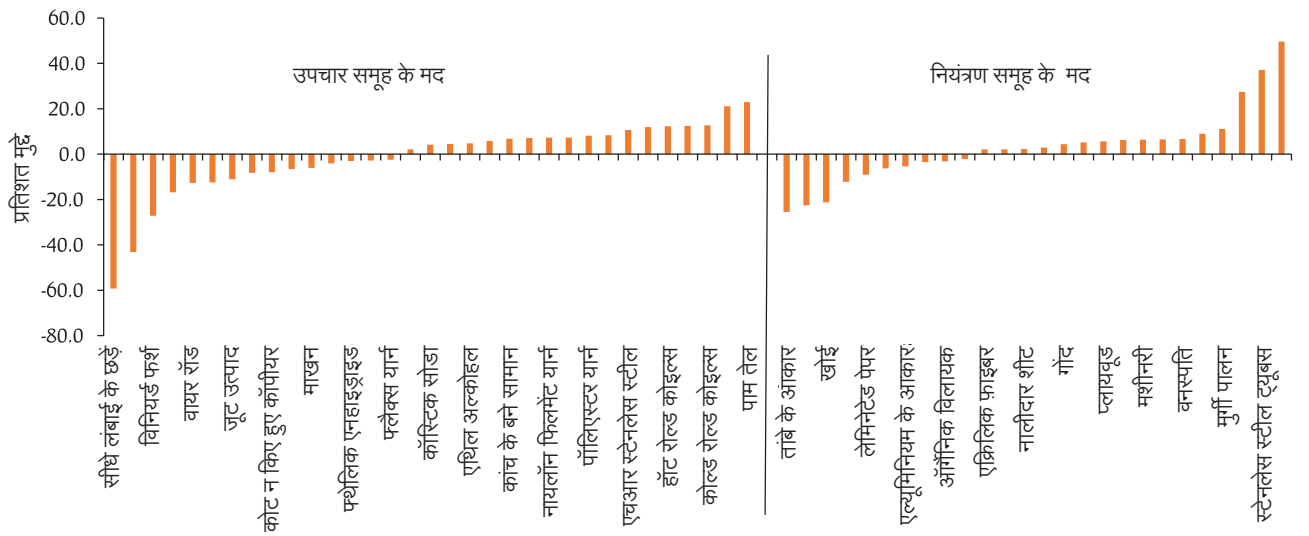

बाद में लगाए जाने और समय के डमी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। पैनल डेटा के साथ डीआईडी का उपयोग करने का फायदा यह है कि आइटम निश्चित प्रभाव और समय निश्चित प्रभाव को अन्य अवलोकन योग्य चर[4] के अलावा भी नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुभवजन्य विनिर्देश इस प्रकार हैं :

$$\underbrace{LIMPV_{it} = \beta_0 + \beta_1 LIIP_{it-1} + \beta_2 LGRIIP_{it-1}}_{\text{(Control variables)}} + \beta_3(Time\ dummy * Product\ dummy) + Product\ FE + Time\ FE + \varepsilon_{it} \qquad \ldots\ldots\ldots(1)$$

यहां, आईआईएमपीवी वस्तुओं की आयात की मात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आश्रित चर है[5]। जबकि आईआईपी,वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, जीआरआईआईपी का तात्पर्य वस्तुओं के समूह के आईआईपी से है, जिसमें से आयात मद[6] शामिल है। आईआईपी ग्रुप को समूह के भीतर संबंधित वस्तुओं की मांग के लिए प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी यह धारणा यह है कि किसी विशेष समूह का उच्च उत्पादन विकास समूह के भीतर की सभी वस्तुओं के लिए उछाल की मांग को प्रतिबिंबित करता है। यह उस समूह के भीतर वस्तुओं के आयात को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, i और t क्रमशः उत्पाद और समय का प्रतिनिधित्व करता है। यहां आयात उपायों का प्रभाव संवादात्मक शब्द के माध्यम से लिया गया है। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर प्रभाव को समझने के लिए, नीचे दर्शाए गए विशिष्ट समीकरण के आधार पर अध्ययन अनुमान का परीक्षण करता है:

$$DLPI_{it,12} = \underbrace{\gamma_0 + \gamma_1 DLIMPV_{it,12} + \gamma_2 DLIIP_{it,12} + \gamma_3\ DLGRINF_{it,12}}_{\text{(Control variables)}} + \gamma_4(Time\ dummy * Product\ dummy) + Product\ FE + Time\ FE + \varepsilon_{it} \qquad \ldots\ldots\ldots(2)$$

समीकरण 2 में, डीएलपीआई निर्भर चर है जो 12 महीने पूर्व (वर्ष दर वर्ष परिवर्तन) की तुलना में अवधि t में किसी आइटम के लॉग मूल्य सूचकांक में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व

4 आइटम निश्चित प्रभाव सभी अप्रचलित छोड़े गए चर को निर्भर करता है जो आश्रित चर को अनुभागीय रूप से प्रभावित करते हैं लेकिन समय के साथ भिन्न नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, माँग की कीमत लोच वस्तुओं में भिन्न हो सकती है, लेकिन समय की पर्याप्त अवधि में नहीं बदलती है। इसी प्रकार, अवधि निश्चित प्रभाव अप्रभावित छोड़े गए चर के प्रभाव को पकड़ लेता है, विशेष रूप से, विनिमय दर में परिवर्तन और अन्य नीतिगत परिवर्तन जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं और समय के साथ भिन्न हो सकते हैं लेकिन निरंतर पार-अनुभागीय हैं। सिद्धांत रूप में, टैरिफ आंशिक रूप से टैरिफ लगाने वाले देश (जीनी 2020) में एक मुद्रा प्रशंसा से ऑफसेट होते हैं और उनके प्रभाव विनिमय दरों (स्टिग्लिट्ज़ 2016) में अंतर्जात गति द्वारा ऑफसेट होने की संभावना है।

5 समीकरणों में L एक वेरिएबल के लॉग को दर्शाता है.

6 चूंकि आयात की मात्रा में वास्तविक वृद्धि कुछ मामलों में असामान्य रूप से अधिक थी, इसलिए इस चर को 100 से विभाजित करके घटाया गया है। उदाहरण के लिए, 10% की आयात मात्रा में वृद्धि 0.10 के रूप में ली जाएगी और इस प्रकार इसके गुणांक के आकार के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए। एंडोजेनिटी को सही करने के लिए, समूह IIP विकास और समूह मुद्रास्फीति को आयात के भारित योगदान के साथ ही पूरा करके समायोजित किया जाता है।

करता है। इसी प्रकार डीलआईएमपीवी,डीएलआईआईपी, डीएलजीआरआईएनएफ क्रमशः आयात मात्रा, घरेलू उत्पादन, समूह मुद्रास्फीति में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन पर हैं। समूह मुद्रास्फीति वस्तुओं के व्यापक समूह की मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व करती है, जो या तो नमूने में कवर की गई वस्तुओं से लंबवत या क्षैतिज रूप से संबंधित होती हैं।

यहां उद्देश्य यह है कि एक ही समूह से संबंधित वस्तुओं की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, जो आयात के उपायों के कारण कम आयात के कारण आपूर्ति की कमी के अलावा अन्य सामान्य कारकों (अर्थात , आपूर्ति की कमी के अलावा अन्य) के प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है।

इन दो समीकरणों में, , $\beta 3$ और $\gamma 4$ हमारे मुख्य हित के गुणांक हैं क्योंकि उनका सांख्यिकीय महत्व आयात मात्रा वृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने में आयात उपायों की प्रभावकारिता को प्रभावित करेगा। समीकरण 1 पर आधारित परिणाम दर्शाते हैं कि IIP का गुणांक काफी नकारात्मक है, जो आयात मात्रा पर घरेलू उत्पादन के व्युत्क्रम कारण का संकेत देता है। पिछले महीने उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि से कम से कम 0.004 प्रतिशत की औसत से कमोडिटी आयात में गिरावट के साथजुड़ा हुआ है। डमी की अंतःक्रियात्मक अवधि नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि आयात उपायों के लागू होने से पश्च कार्यान्वयन की अवधि (तालिका 4) में आयात मात्रा में गिरावट आती है। इंट्रैक्शन टर्म का मतलब है कि इंपोर्ट प्रतिबंध समूह को नियंत्रित करने की तुलना में आयात प्रतिबंधात्मक उपाय लागू होने के बाद आयात की मात्रा औसतन 1.3 प्रतिशत घट जाती है। अन्य नियंत्रण चर, अर्थात , समूह IIP के संबंध में, परिणाम यह बताता है कि संबंधित वस्तु समूह में मांग की स्थिति सकारात्मक रूप से आयात की मांग को प्रभावित करती है।

मुद्रास्फीति समीकरण में, बातचीत शब्द का गुणांक (अर्थात, $\gamma 4$) सकारात्मक है जो बताता है कि मुद्रास्फीति प्रतिबंधात्मक उपायों के लागू होने के साथ अधिक होती है, हालांकि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन में बदलाव नमूने में शामिल वस्तुओं के मुद्रास्फीति के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तालिका 5 अनुमान प्रदान करती है कि उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि मुद्रास्फीति में 0.008 प्रतिशत की गिरावट के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा, आयात की मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के घरेलू मुद्रास्फीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो कि हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार नहीं है। आम तौर पर इस तरह के संबंध की वृहद स्तर पर उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उच्च आयात से घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास होता है जो बदले में मुद्रास्फीति को विनिमय दर के माध्यम से प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, कमोडिटी स्तर पर, गुणांक का संकेत आयातित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रुझान से निर्धारित किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि समूह की मुद्रास्फीति में परिवर्तन आयातित वस्तुओं की मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण बदलाव की व्याख्या करता है। इससे पता चलता है कि समान

सारणी4: पैनल डेटा पर आधारित अंतर-अंतर अनुमान (आश्रित चर :एलआईएमपीवी)

	कोईएफएफ	एस. ई	जेड	पी-मूल्य
सी	0.11	0.01	10.18	0.00
एल आई आई पी(-1)	-0.004	0.002	-2.21	0.03
एल जी आरआईआईपी (-1)	0.01	0.00	1.48	0.14
सहभागिता टर्म	-0.01	0.01	-2.26	0.02
के लिए नियंत्रित				
मद स्थिर प्रभाव	Yes			
निर्धारित अवधि प्रभाव	Yes			
आर 2	0.75			

टिप्पणी: सफेद- अवधि –भार का प्रयोग करते हुए अवलोकन के कल्सटरिंग के लिए मानक त्रुटियाँ(कोष्ठक में) को सुधार किया गया।

सारणी5: पैनल डेटा पर आधारित अंतर-अंतर अनुमान (आश्रित चर :डीएलओजीपीआई,अर्थात मुद्रास्फीति)

	कोईएफएफ	एस. ई	जेड	पी-मूल्य
सी	0.007	0.002	3.69	0.00
डीएलआईएमपीवी	0.004	0.001	3.74	0.00
डीएलआईआईपी	-0.008	0.004	-2.21	0.03
डीएलजीआरआईएनएफ	0.886	0.018	49.85	0.00
सहभागिता टर्म	0.008	0.006	1.25	0.21
के लिए नियंत्रित				
मद स्थिर प्रभाव	Yes			
निर्धारित अवधि प्रभाव	Yes			
आर ^{2}	0.29			

टिप्पणी: सफेद- अवधि –भार का प्रयोग करते हुए अवलोकन के कल्सटरिंग के लिए मानक त्रुटियाँ(कोष्ठक में) को सुधार किया गया।

कारक, जो अन्य समूह की वस्तुओं की मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं (या तो क्षैतिज या लंबवत रूप से संबंधित) आयात उपायों वाली वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

V. निष्कर्ष

व्यापक समष्टि आर्थिक संकेतकों पर आयात उपायों के प्रभाव को समझने पर साहित्य में व्यापार ढांचे के निष्कर्षों से प्रेरित, यह अध्ययन भारत के लिए मामले की जांच करता है। अध्ययन दो परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है। पहला, क्या आयात उपायों का सामना करने वाली वस्तुओं के आयात की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, क्या आयात उपायों को अपनाने के बाद इन वस्तुओं की घरेलू मुद्रास्फीति दर में तेजी आती है। 119 वस्तुओं के लिए पैनल डेटा पर डीआईडी विधि का उपयोग करके परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है।

परिणाम बताते हैं कि ये आयात उपाय, कार्यान्वयन के बाद की अवधि में आयात मात्रा को प्रभावित करते हैं। यद्यपि मुद्रास्फीति पर प्रभाव सिद्धांत के अनुरूप है, गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रास्फीति पर नगण्य प्रभाव संभवतः यह दर्शाता है कि आयात माप के लिए जिन वस्तुओं के आयात की मात्रा पर विचार किया जा रहा है, वह कीमतों को प्रभावित करने के लिए घरेलू आपूर्ति के सापेक्ष पर्याप्त नहीं है, हालांकि मात्रा डेटा की कमी के कारण इस अनुमान को अनुभवजन्य रूप से पता लगाना मुश्किल है। घरेलू आपूर्ति पर। संक्षेप में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आयात उपाय इन वस्तुओं के आयात की मात्रा में वृद्धि को प्रभावित करते हैं लेकिन उनकी मुद्रास्फीति को नहीं। हालांकि, अनुमान को चेतावनी के साथ देखने की जरूरत है कि अन्य चर पर तुलनीय डेटा की अनुपलब्धता के कारण कई आयात आइटम नमूने में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, गणना एक आंशिक संतुलन ढांचे पर आधारित होती है जिसके तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि आयात उपाय उन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं जो माप से सीधे प्रभावित आयात का उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी, अध्ययन आयात मात्रा और मुद्रास्फीति पर आयात प्रतिबंधात्मक उपायों के कारण प्रभावों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षणवाद पर मौजूदा साहित्य के अनुरूप हैं।

संदर्भ

Alfaro, L. (2005), "Inflation, openness, and exchange-rate regimes: the quest for short-term commitment". *Journal of Development Economics*, *77*(1), 229-249.

Amiti, M., Redding, S. J., and Weinstein, D. E. (2019), "The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare". *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187-210.

Barattieri, A., Cacciatore, M., and Ghironi, F. (2018), "Protectionism and the business cycle". *National Bureau of Economic Research*, Working Paper 24353.

Bown, C. P. (2010), "Global antidumping database". *World Bank.*

Bown, C. P. (2011), "Taking Stock of Antidumping, Safeguards and Countervailing Duties, 1990-2009". *The World Economy* 34: 1955-1998.

Bown, C. P., and Crowley, M. A. (2012), "Import protection, business cycles, and exchange rates: Evidence from the Great Recession". *World Bank.*

De Loecker, J., J. Eeckhout, and G. Unger (2018), "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications". *National Bureau of Economic Research*, Working Paper 23687.

Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J., and Khandelwal, A. K. (2020), "The return to protectionism". *The Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 1-55.

Goldberg, P. K., Khandelwal, A. K., Pavcnik, N., and Topalova, P. (2010). "Imported intermediate inputs and domestic product growth: Evidence from India". *The Quarterly journal of economics*, *125*(4), 1727-1767.

Irwin, D. A. (2019), "Does Trade Reform Promote Economic Growth? A Review of Recent Evidence". *National Bureau of Economic Research*, Working Paper 25927.

Lazer, D. A. (1999), "The free trade epidemic of the 1860s and other outbreaks of economic discrimination", World Politics, Vol. 51, 447–83.

Li, M. (2020). The US-China trade war: Tariff data and general equilibrium analysis. Journal of Asian Economics, 101216.

Marx, K., & Engels, F. (1848), "The Communist Manifesto". Selected Works by Karl Marx and Frederick Engels. New York: International Publishers, 1363.

Jeanne, Olivier (2020), "To What Extent Are Tariffs Offset by Exchange Rates?", PIIE Working Paper No.20-1, January.

Kim, M., Beladi, H. (2005), "Is Free Trade Deflationary". *Economics Letters*, 89: 343-349.

Kreinin, Mordechai E. (1961), "Effect of Tariff Changes on the Prices and Volume of Imports" The American Economic Review, Vol. 51, No. 3, 310-324

Nicita, Alessandro (2019), "Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China", UNCTAD Research Paper No. 37, UNCTAD/SER.RP/2019/9.

Rodrik, D. (2009), "The myth of rising protectionism". *Project Syndicate*

Romer, D. (1993), "Openness and inflation: theory and evidence". *The Quarterly Journal of Economics*, *108*(4), 869-903.

Selina Jackson(2015), "Growth and development: Why openness to trade is necessary but not sufficient", https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/11/23/growth-and-development-why-openness-to-trade-is-necessary-but-not-sufficient/

Stiglitz, Joseph. (2016), "A Nobel Laureate Explains How Trump Could Nuke the Economy", Vanity Fair, December 27.

World Trade Organisation Report (2011), "The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence".

परिशिष्ट

नमूने में शामिल वस्तुओं की सूची और उनके लिए किए गए आयात उपाय

क्रम संख्या	पण्य	दिनांक	आयात उपायों के प्रकार
1	शीट ग्लास	13-03-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
2	स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद	05-06-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
3	दूध	24-06-2015	आयात पर प्रतिबंध
4	दूध के उत्पाद	24-06-2015	आयात पर प्रतिबंध
5	फाइबर ग्लास	09-07-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
6	गेहूँ	07-08-2015	आयात पर प्रतिबंध
7	कास्टिक सोडा	18-08-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
8	फॉस्फोरिक एसिड	24-08-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
9	एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडाइन रबर	04-09-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
10	प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	04-12-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
11	फ्थेलिक एनहाइड्राइड	04-12-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
12	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	11-12-2015	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
13	विस्कोस स्टेपल फाइबर	08-08-2016	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
14	हॉट रोल्ड (एच आर) कॉइल्स और शीट्स	08-08-2016	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
15	मार्बल स्लैब, ट्रैवर्टीन	17-09-2016	आयात पर प्रतिबंध
16	मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के तार रॉड	02-11-2016	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
17	जूट उत्पाद (यार्न और हेसियन)	05-01-2017	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
18	मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	07-02-2017	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
19	विस्कोस फिलामेंट यार्न	03-05-2017	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
20	सोडा पाउडर	30-06-2017	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
21	चीनी	10-07-2017	आयात ड्यूटी
22	पिजन मटर	05-08-2017	आयात पर प्रतिबंध
23	पाम तेल (कच्चा और परिष्कृत)	11-08-2017	बेसिक कस्टम ड्यूटी
24	उड़द / मूंग दाल	21-08-2017	आयात पर प्रतिबंध
25	सोयाबीन	17-11-2017	बेसिक कस्टम ड्यूटी
26	क्रूड सोयाबीन तेल	17-11-2017	बेसिक कस्टम ड्यूटी
27	विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान (टीवी)	14-12-2017	बेसिक कस्टम ड्यूटी
28	चिकपेस और मसूर	21-12-2017	बेसिक कस्टम ड्यूटी
29	यूरिया	24-01-2018	आयात पर प्रतिबंध
30	विनियर्ड इंजीनियर लकड़ी का फर्श	27-03-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
31	कांच के सामान	18-04-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
32	पेरॉकसो सल्फेट	14-05-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
33	अखरोट	23-05-2018	आयात पर प्रतिबंध
34	संतृप्त फैटी शराब	25-05-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
35	बादाम	01-06-2018	आयात पर प्रतिबंध
36	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	01-06-2018	आयात पर प्रतिबंध
37	दलहन	20-06-2018	टैरिफ़
38	उच्च तम्बू पॉलिएस्टर यार्न	09-07-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
39	पीस मीडिया बॉल्स	13-07-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
40	सौर सेल	30-07-2018	सुरक्षा ड्यूटी
41	एथिल अल्कोहल	21-08-2018	आयात पर प्रतिबंध
42	पेट्रोलियम तेल	21-08-2018	आयात पर प्रतिबंध
43	कांच	06-09-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
44	फ्लैट बेस स्टील	05-10-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
45	नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न	05-10-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
46	डक्टाइल आयरन पाइप	09-10-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
47	सीधे लंबाई बार और छड़	18-10-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
48	फ्लैक्स यार्न	18-10-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
49	एसिड	15-11-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
50	लेप न किए हुए कापियर	04-12-2018	एंटी-डंपिंग ड्यूटी